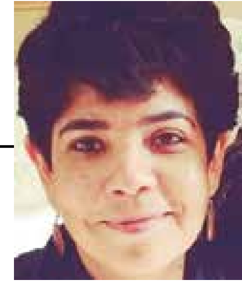
ग्रीन स्कूल कार्यक्रम: कक्षा के बाहर का एक अनुभव

सुमिता दासगुप्ता



पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान हमने पर्यावरण को उसके विभिन्न अवतारों के रूप में भारत के शिक्षा क्षेत्र में शामिल होते देखा है। कभी–कभी 'मुख्यधारा के विषयों' की सेविका के रूप में, जब इसे रसायन शास्त्र या इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के पन्नों के बीच में भर दिया जाता है या कई बार सभी पाठ्येत्तर गतिविधियों की साझा विषयवस्तु के रूप में ठूँस दिया जाता है, जैसे स्थानीय जीव–जन्तुओं पर स्क्रैपबुक बनाने के लिए स्थानीय उद्यानों में बच्चों को 'प्रकृति भ्रमण' करा देना। पर अब तक कभी भी यह औपचारिक ग्रेड देने वाली व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। पर देश की सर्वोच्च पाठ्यक्रम निर्धारण संस्था और दो प्रभावशाली शिक्षा बोर्डों ने स्कूल की महत्त्वपूर्ण अन्तिम परीक्षाओं में पर्यावरण के लिए अंक निर्धारित करने का निर्णय ले लिया, तो उसकी गौण भूमिका समाप्त हो गई। ऐसे परिदृश्य में जहाँ एक–एक अंक को भविष्य में कैरियर बनाने की सीढ़ी के रूप में देखा जाता है, इससे अधिक महत्त्वपूर्ण कदम नहीं हो सकता था, खासतौर पर तब, जब उसके साथ कुछ और रोचक शर्तें भी जोड़ दी गईं। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन पारम्परिक 'पाठ्यपुस्तकें पढ़ो, परीक्षा दो' वाले तरीके पर आधारित नहीं होगा। विद्यार्थियों के ग्रेड इस बात पर निर्भर करेंगे की वे 'जमीन पर' कितने सक्रिय रहे।

जाहिर है, कि इस आदेश के जारी होने के बाद हड़बड़ी में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। पर्यावरण को एक जीते जागते, साँस लेते और 'करने वाले' विषय के रूप में लेना ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया हो। इसके लिए न तो कोई पहले से तैयार ऐसे स्रोत हैं, न ऐसी पाठ्यपुस्तकें और न ही ऐसी सन्दर्भ पुस्तकें हैं जो इस साँचे में माफिक बैठती हों। पर हमेशा की तरह, नई–नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की अपनी क्षमता का फिर एक बार प्रदर्शन करते हुए, इसके शिक्षक कुछ असाधारण युक्तियों के साथ सामने आए ताकि पर्यावरण को एक ठोस, सुनिश्चित और साकार (ग्रेड दिए जा सकने लायक) विषय बनाया जा सके।

ग्रीन स्कूल्स (हरित स्कूल) कार्यक्रम[1] (जी.एस.पी.), जो दिल्ली–स्थित सेण्टर फॉर साइंस एण्ड एन्वायरन्मेंट (सी.एस.ई.) का एक प्रमुख अभियान है, शिक्षकों की मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि यह कार्यक्रम इस बात को मानता है कि पर्यावरण की इस कक्षा का महत्त्व सबसे अधिक है। एक विषय के रूप में पर्यावरण को इस ग्रह के आने वाले संरक्षकों के समक्ष एक नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में इसे एक और उबाऊ विषय नहीं बनने दिया जा सकता। इसलिए पर्यावरण को 'करके' सीखने के उपकरण के रूप में जी.एस.पी. की रचना की गई है, क्योंकि करके सीखने का तरीका ही विद्यार्थियों और शिक्षकों को कक्षाओं से बाहर आकर चीजों को करने (जैसे गिनना, वजन लेना, मापना, खोजना और विश्लेषण करना) के लिए प्रेरित करता है। जी.एस.पी. मार्गदर्शक पुस्तिका, खुद से चीजें करने की ऐसी पुस्तिका है जिसमें यह बताया गया है कि स्कूल के अहाते के भीतर ही पानी, हवा, ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थ और भूमि का लेखा परीक्षण कैसा किया जाए। ऐसी मार्गदर्शक पुस्तिका के साथ जी.एस.पी. इन प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धक के रूप में स्कूल समुदाय के प्रदर्शन का आकलन करने की एक नई कार्यविधि सामने लेकर आया है। इसका अन्तिम उत्पाद एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसे बनाने में

[1]वर्तमान में 22 राज्यों और 1 केन्द्र शासित प्रदेश के करीब 30,000 स्कूल जी.टी.जी.एस.पी. (गोबर टाइम्स ग्लोबल स्कूल्स प्रोग्राम) नेटवर्क का हिस्सा हैं। सी.एस.ई. ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम और उत्तराखण्ड की राज्य सरकारों के साथ औपचारिक भागीदारी की है। इस गठजोड़ के मुताबिक राज्य स्तरीय केन्द्रीय (नोडल) एजेंसी 50–60 प्रधान प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सी.एस.ई. को आमंत्रित करती है। फिर, जी.एस.पी. द्वारा प्रशिक्षित ये लोग पर्यावरण का लेखा परीक्षण करने के लिए जिले व ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों में जी.एस.पी. मार्गदर्शक पुस्तिका को क्षेत्रीय भाषा में अनुदित कर दिया गया है ताकि सभी स्तरों के शिक्षक इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। इस प्रक्रिया ने जी.एस.पी. के सन्देश को इन राज्यों के हर एक कोने में पहुँचाने में मदद की है। दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों की भागीदारी भी हर साल कई गुना बढ़ती गई है। दूसरे राज्यों में, जी.एस.पी. दल ऐसे छोटे/स्थानीय एन.जी.ओ. तथा शैक्षणिक संस्थाओं के साथ भागीदारी करता रहा है, और उन्हें प्रशिक्षित करता रहा है जिनके पास स्कूलों का एक ऐसा तंत्र है जो उनके अन्तर्गत काम करता है। भागीदारों में चार राज्यों – दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश – ने मुख्यमंत्री जी.एस.पी. पुरस्कार देना शुरू किए हैं जो राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य भागीदारों की मेहनत को स्वीकार करना तथा और अधिक भागीदारों को प्रोत्साहित करना है, साथ ही इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि राज्य की एजेंसियाँ इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाती रहें और उनके पास एक दीर्घकालिक योजना रहे। श्रीलंका और यूएई की सरकारों ने भी जी.एस.पी.को उनके राष्ट्रीय पर्यावरण पाठ्यक्रम के एक अंश के रूप में अपना लिया है।

सी.एस.ई. स्कूल समुदाय की मदद करता है। इस रिपोर्ट कार्ड में स्कूल समुदाय खुद की उपलब्धियों का मात्रात्मक आकलन करता है। साथ ही ऐसी कमियों की पहचान भी करता है जिन पर और अधिक जागरूकता और सजगता दिखाने की जरूरत है। इस लेखा परीक्षण के लिए कोई विशेष उपकरण या धनराशियों की जरूरत नहीं पड़ती। सी.एस.ई. स्कूलों को यह सिखाता है कि ऐसी सरल तकनीकों का उपयोग करके, जो वैसे भी स्कूल की रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा होती हैं, आँकड़े कैसे इकट्ठा करना होते हैं। दरअसल ये गतिविधियाँ तो मुख्यधारा के पाठ्यक्रम के किसी भी विषय के लिए भी उपयोग की जा सकती हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से जी.एस.पी. द्वारा इस सन्देश को सभी सम्बन्धित पक्षों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है कि 'पर्यावरण' शब्द के निहितार्थ सिर्फ पेड़ों, पक्षियों और बाघों तक ही सीमित नहीं है। इसमें वे सारे प्रमुख घटक शामिल होते हैं जिनसे किसी मनुष्य का जीवन और उसकी जीविका बनती है। इस रिपोर्ट कार्ड में स्कूल अपनी उपलब्धियों का मात्रात्मक आकलन करता है। साथ ही उन कमियों की पहचान करता है जिनकी तरफ और अधिक जागरूकता और सजगता दिखाने की जरूरत होती है।

इस कार्यक्रम के अन्त में सी.एस.ई. एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करता है जिसे गोबर टाइम्स ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम पुरस्कार समारोह कहा जाता है। यहाँ देशभर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और व्यक्तियों को उनके उद्यम और नूतन कौशलों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इस पुरस्कार समारोह का उद्देश्य भागीदारों द्वारा किए गए प्रयासों को पहचान देने के साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को आगे आकर इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और भारतवर्ष के हर हिस्से के स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया जाता है। उन्हें इस पुरस्कार समारोह को देखने के लिए ही आमंत्रित नहीं किया जाता बल्कि समारोह के अन्तर्गत होने वाली चित्रकला प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने, नुक्कड़ नाटकों में अभिनय करने, फिल्में देखने और एक–दूसरे के साथ घुलने–मिलने का अवसर भी दिया जाता है। हर साल कम से कम सर्वश्रेष्ठ 20 स्कूलों में से कम से कम 5 से 8 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं।

पर क्या जी.एस.पी. काम कर रहा है?

स्कूली समुदाय पर जी.एस.पी. का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है यदि हम हर गुजरते साल के साथ भागीदारी करने वाले स्कूलों के प्रदर्शन की तुलना करें। यहाँ यह बात ध्यान में रखना महत्त्वपूर्ण है कि इन स्कूलों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा स्कूल साल दर साल लेखा परीक्षण की इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य किसी स्पर्धा को जीतना नहीं रहा है, बल्कि इस बात को भी आँकना है कि क्या वे रिपोर्ट कार्ड को सुधार पाने में सफल रहे हैं और पर्यावरण के बेहतर प्रबन्धक बने हैं।

बदलती हुई प्रवृत्तियाँ और दृष्टिकोण

2006 में, जब लेखा रिपोर्टों का पहला समूह प्रस्तुत किया गया और उनका विश्लेषण किया गया, तो सी.एस.ई. ने निम्नलिखित प्रवृत्तियों की पहचान की :

- पर्यावरण–सम्बन्धी कार्यक्रमों को अभी भी पाठ्येत्तर माना जाता है। अभी भी जीवनशैली या जीवन से जुड़ी आदतों में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए कोई ढाँचागत पद्धति दिखाई नहीं देती।
- स्कूल ऊर्जा और पानी का संरक्षण करने के लिए नवीन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन नए तरीकों के प्रभाव को मापने और उनके परिमाण को निर्धारित करने वाली अगली प्रक्रिया नदारद है।

उदाहरण के लिए, भागीदारी करने वाले 75 स्कूलों ने वर्षाजल संग्रहण प्रणालियाँ स्थापित करवा ली थीं, लेकिन सिर्फ एक स्कूल उसकी वास्तविक क्षमता का उपयोग कर रहा था। दूसरे स्कूलों के लिए यह बस एक प्रदर्शन के नमूने जैसा था – एक बार स्थापित कर दिया और फिर भूल गए। 95 प्रतिशत स्कूल अपशिष्ट पदार्थों के प्रबन्धन के तरीकों पर काम कर रहे थे, जैसे केंचुआ खाद बनाना और कागज की री–सायक्लिंग। लेकिन सिर्फ 5 स्कूल ऐसे थे जो इस बात का ब्यौरा रख सके कि उनके अहातों में दरअसल कितना प्रति व्यक्ति अपशिष्ट पदार्थ बन रहा था।

2007 में निम्नलिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत लोगों के रवैयों और उनके नजरियों में असाधारण बदलाव देखने को मिला :

- स्कूलों ने एक वर्ष के भीतर ही लेखा परीक्षण की कला में निपुणता हासिल कर ली थी।
- उनके द्वारा किए गए आँकड़ा–संग्रह, सारणीकरण, और विश्लेषण का स्तर उत्कृष्ट था।

- वर्षाजल संग्रहण, पानी और अपशिष्ट पदार्थों का री–सायक्लिंग कहीं ज्यादा बारीक, ढाँचागत और सटीक थे।
- जाहिर था कि विद्यार्थी पूरे कार्यक्रम के हर चरण में शामिल थे। उनकी जागरूकता का स्तर भी बहुत बढ़ गया था।

उदाहरण के लिए हर स्कूल ने विद्यार्थी समूहों को अपशिष्ट पदार्थ को तौलने का जिम्मा सौंपा था। लेखा परीक्षण दलों में झाड़ू लगाने वाले, माली, अपशिष्ट पदार्थों को ठिकाने लगाने वाले लोग शामिल थे। विद्यार्थियों ने स्प्रिंग तराजू, हाथ में लेने वाला तराजू और भार तोलने की मशीन का इस्तेमाल किया और वे सी.एस.ई. को यह बता पाए कि उनके स्कूल में किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ पैदा हो रहे थे। यह भी बता रहे थे कि प्रतिदिन कितना अपशिष्ट पैदा हो रहा था।

भागीदारों की प्रतिबद्धता और लगन ने 2008 में सी.एस.ई.को पुरस्कारों की एक नई श्रेणी शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसका नाम रखा गया चेंज मेकर्स (बदलाव लाने वाले लोग)। ये पुरस्कार उन स्कूलों को दिए गए जो न सिर्फ स्कूली समुदाय की, बल्कि विद्यार्थियों के माता–पिता तथा उनके आसपास के लोगों की सोच और जीवनशैली में बुनियादी, किन्तु साथ ही दीर्घकालिक बदलाव लाने में सफल रहे थे। उदाहरण के लिए दक्षिण दिल्ली के एक स्कूल में रोज स्कूल पहुँचने के लिए लोगों की आदतों में 8 प्रतिशत का बदलाव देखा गया। विद्यार्थी तथा स्कूल के शिक्षक–कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत कारों या दुपहिया वाहनों के बजाय सार्वजनिक यातायात के साधनों (इनमें से कुछ स्कूल द्वारा ही मुहैया कराए गए वाहन थे) का इस्तेमाल करने लगे थे। बच्चों के माता–पिता भी उनके इस निर्णय में शामिल थे और वे भी इस पहल के भागीदार थे।

तब से लेखा परीक्षण की यह प्रक्रिया संसाधनों की स्थिति पर प्रामाणिक आँकड़े जुटाने का तथा सम्बन्धित लोगों की प्रवृत्तियों को पहचानने का बेहद प्रभावी माध्यम बन चुकी है। यह प्रक्रिया इन बातों को स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि बेहतर स्थिति के लिए क्या, कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए। इसलिए इस प्रक्रिया को अब प्रशासकों द्वारा इस बात का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि लागू की गई किसी व्यवस्था या नीति ने अभी तक अच्छे नतीजे दिए हैं या नहीं।

उदाहरण के लिए दिल्ली के स्कूलों ने सी.एन.जी. द्वारा चलित वाहनों की वजह से ऊर्जा के लेखा परीक्षण में जबरदस्त सुधार हासिल किया है। इस नीति ने उन्हें दूसरे राज्यों की तुलना में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद की है। पर कभी–कभी रिपोर्ट कार्ड में इन स्कूलों के अंक बहुत कम हो जाते हैं जिसका कारण है डीजल द्वारा चलने वाले जेनेरेटरों पर इन स्कूलों की बढ़ती निर्भरता। यह स्थिति दिल्ली शहर में बिजली की स्थिति को दर्शाती है।

जी.एस.पी. क्यों?

यह बात बहुत स्पष्ट है कि यह लेखा परीक्षण हर स्कूल के लिए जरूरी है, खासतौर से ऐसे स्कूलों में जहाँ संसाधनों की कमी है। ऐसे स्कूलों में लेखा परीक्षण की मदद से इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है कि स्कूल की बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहें। ऐसे स्कूलों में जहाँ संसाधनों का अतिरेक हो, इस लेखा परीक्षण का उपयोग संसाधनों की बरबादी रोकने के लिए किया जा सकता है।

इसलिए जी.एस.पी. का उपयोग स्कूली प्रशासन द्वारा ऐसे उपकरण के रूप में किया जा सकता है जिससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला, दिल्ली के स्कूलों के लिए व्यावहारिक, हासिल किए जा सकने वाले 'ग्रीन नॉर्म्स (पर्यावरण मानक)' तय करना, और फिर अगला कदम उठाते हुए, पर्यावरण–हितैषी नीतियों और आधारभूत ढाँचे के रूप में इन मानकों को स्कूलों में लागू करना।

पर क्या स्कूल जमीन पर ऐसा कर रहे हैं?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ उस पत्र का जिक्र करूँगी जो हाल ही में हमें अपने एक वरिष्ठ स्कूली साझेदार द्वारा प्राप्त हुआ था। इस पत्र में कहा गया है, 'जैसा कि आप जानते हैं, हमारा स्कूल दक्षिण दिल्ली के सबसे सूखे इलाकों में से एक में स्थित है। हर साल गर्मियों में हमें मजबूर होकर व्यावसायिक दरों पर पानी खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारे यहाँ सी.एस.ई. कार्यक्रम लागू होने के बाद से हम लोग अपनी खपत को कम करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। और हमने आखिरकार ऐसा कर पाने का रास्ता ढूँढ़ लिया है। हमने अपने स्कूल के सभी अठारह पुरुष शौचालयों को जलरहित इकाइयों में तब्दील कर दिया है। यह ऐसा कदम है जो प्रति वर्ष 1,70,000 लीटर ताजा पानी बचाएगा। इस व्यवस्था पर हमें प्रति इकाई 2500 रुपए का खर्चा आता है। इस प्रणाली को लगाने की लागत पहले ही महीने में पानी की होने वाली बचत से निकल आती है।'

संसाधनों की बरबादी करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं से लेकर, जिनके मन में इस बात का अपराध बोध है, जानकार पर सजग संसाधन प्रबन्धक बनने तक, जी.एस.पी. गुरुओं ने बहुत लम्बा रास्ता तय किया है। यह वाकई एक सुखद व प्रेरणादायी बात है। आज वैश्विक मंच पर पर्यावरण ने केन्द्रीय स्थान हासिल कर लिया है। यह अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप तय करने, नीतियों को प्रभावित करने तथा राष्ट्राध्यक्षों के भाग्य का निर्णय करने में अहम भूमिका निभाता है। आन्तरिक रूप से, यह समस्त क्षेत्रों (उद्योग से लेकर कृषि तक) के एजेंडे में एक प्राथमिक मुद्दा बन चुका है। तो समय आ गया है कि हम आबादी के सबसे महत्त्वपूर्ण भाग, विद्यार्थियों को भी इस चर्चा में शामिल करें। अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि इन मुद्दों को लेकर हम विद्यार्थियों के कौशलों का विकास करें तथा इससे सम्बन्धित उनके ज्ञान की बुनियाद को और गहरा करें। जी.एस.पी. जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को उनकी सोच को व्यक्त करने का मंच तो देते ही हैं, साथ ही जमीन पर प्रयोग करने का मौका भी देते हैं।

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवराली, सिक्किम: यहाँ पर जी.एस.पी. की पूरी लेखा परीक्षण प्रक्रिया के बारे में एक नया ही दृष्टिकोण अपनाया गया है। इन लोगों ने इस प्रक्रिया को स्वास्थ्य से जोड़ दिया है। उत्तरी सिक्किम की पहाड़ियों पर स्थित इस छोटे से स्कूल की लड़कियाँ 2005 तक एक बहुत सक्रिय हेल्थ क्लब (स्वास्थ्य मण्डली) चलाती थीं। जी.एस.पी. से परिचय होने तक ये लड़कियाँ विद्यार्थियों तथा शिक्षकों–कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार दिया करती थीं और स्कूल की सामान्य साफ–सफाई का निरीक्षण करती थीं। सिक्किम की ये चतुर नागरिक जल्दी ही इस बात को समझ गईं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितनी जरूरी दवाइयाँ और पट्टियाँ होती हैं, अगर उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही जरूरी स्कूल में पैदा होने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबन्धन करना था, साफ–सुथरे तथा पानी की बचत करने वाले शौचालयों की व्यवस्था करना था और यह सुनिश्चित करना था कि जो पानी वे लोग पी रहे थे वह सुरक्षित हो। तो उनका हेल्थ क्लब पर्यावरण सम्बन्धी गतिविधियों का केन्द्र बन गया था। स्कूल वाकई पहले से अधिक स्वस्थ हो गया था।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मकरेरी, हिमाचल प्रदेश: पहाड़ों के क्षेत्र में एक और भागीदार स्कूल। यह स्कूल हिमाचल प्रदेश का है तथा यह और भी दूर–दराज इलाके में स्थित है। पर राज्य के बहुत भीतरी इलाके में, सबसे करीबी जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर स्थित होने की स्थिति भी इस बेहद ऊर्जावान स्कूली समुदाय के भीतर कभी हताशा का भाव नहीं भर पाई है। इस स्कूल ने स्थानीय जैव–विविधता को संरक्षित रखने के अपने कार्य (पारम्परिक अनाजों का बीज बैंक बनाना तथा पौधों की स्थानीय प्रजातियों की कलमें रखना) के लिए कई पर्यावरण पुरस्कार जीते थे। पर्यावरण के प्रति पहले से सजग इन लोगों को जी.एस.पी.से यह संदेश मिला कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़, पौधे, जानवर और बीज नहीं होता, बल्कि पर्यावरण के भीतर पानी, ऊर्जा और अपशिष्ट पदार्थ भी शामिल होते हैं; और यह कि सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं पर इतना जोर देने वाले हिमाचल जैसे राज्य के लिए यह अत्यावश्यक था कि वहाँ वर्षा जल संग्रहण प्रणालियों का उपयोग शुरू किया जाए, ताकि नदी तलों के सूखने पर खेतों में पानी के आसन्न संकट से निपटा जा सके। इस बात का स्मरण दिलाए जाने के बाद से ही वे लोग इस ओर अग्रसर हो गए। लेखा परीक्षण दलों ने स्थानीय पंचायत को काफी समझाया–मनाया, संसाधन जुटाए और यह सुनिश्चित किया कि न सिर्फ स्कूल में बल्कि गाँव में भी वर्षाजल संग्रहण से जुड़े ढाँचे स्थापित हों।

जी.एस.पी. की भविष्य की सोच क्या है?

सी.एस.ई. का लक्ष्य प्रत्येक राज्य सरकार के साथ जी.एस.पी. भागीदारी निर्मित करना तथा उन सारे राज्यों में सीएम–जी.एस.पी. पुरस्कारों की शुरुआत करना है। सी.एस.ई. अब जी.एस.पी. में निम्नलिखित जिम्मेदारियों को भी शामिल करने के लिए तत्पर है :

- कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों, विद्यार्थियों और स्कूल प्रशासकों में क्षमता निर्माण करना।
- ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के स्कूलों को संसाधनों से लैस करना, सशक्त बनाना, व्यावहारिक व हासिल किए जा सकने वाले 'पर्यावरण मानक' तय करना। फिर इन मानकों को जमीन पर पर्यावरण नीतियों के रूप में

क्रियान्वित करने में तथा स्कूल के अहातों में निभाए जाने में स्कूलों की मदद करना।

- वैकल्पिक पाठ्यक्रम विकसित करने में मदद करना। पहले से ही जी.एस.पी. कई स्कूलों में माध्यमिक और उच्च स्तर के विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) करने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पर जी.एस.पी. की मुख्य चुनौती रही है कि विद्यार्थियों को ऐसा मौका देना कि वे पर्यावरण के बारे में एक और पाठ्यपुस्तक को रटकर सीखने के बजाय 'करके' सीखें। नया पाठ्यक्रम यह संदेश देने का प्रयास करेगा कि 'पर्यावरण' शब्द का आशय सिर्फ पेड़ों, पक्षियों और बाघों तक ही सीमित नहीं है। इसमें वे सारे घटक शामिल हैं जो किसी मनुष्य का जीवन और उसकी जीविका को निर्मित करते हैं।

सुमिता दासगुप्ता ने अपना कैरियर मुख्यधारा की पत्रकार के रूप में शुरू किया था। दिए गए कार्य की जरूरत के मुताबिक उन्होंने राजनीति से लेकर फैशन तक तमाम विषयों पर लिखा है। सेण्टर फॉर साइंस एण्ड एनवायरन्मेंट में पहुँचने के बाद वे अपने रुचि के क्षेत्र के प्रति ज्यादा सजग हुई। उन्होंने सेण्टर की पाक्षिक पत्रिका, डाउन टू अर्थ की उप–सम्पादक के रूप में कार्य करना शुरू किया। बाद में उन्होंने जैव–विविधता के बारे में एक विशेषज्ञ लेखिका के रूप में अपना योगदान दिया और संगठन की प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन इकाई की कमान अपने हाथ में ली। पर शोधकर्ता के बजाय लेखक की भूमिका उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचती रही। तो जब उन्हें पर्यावरण शिक्षा इकाई के कार्यक्रम निदेशक की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने इसे तुरन्त ही स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे उन्हें अपनी दो भूमिकाओं : पहली, सी.एस.ई. के सबसे शुरुआती शिक्षा अभियान, जी.एस.पी. की शुरुआत करना और उसे आगे बढ़ाना तथा दूसरी, विद्यार्थियों के लिए निकलने वाली मासिक पत्रिका गोबर टाइम्स की सम्पादक होना – को जोड़ने का मौका मिल रहा था। वर्तमान में वे विषयवस्तु परामर्शदाता के रूप में काम कर रही हैं और विकास के क्षेत्र से जुड़े मुद्दों में उनकी विशेषज्ञता है। उनसे dasgupta.sumita@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।